DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
नई दिल्ली | बुधवार, 19 जुलाई 2023

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

असर

साबरमती नदी जैसा रिवरफ्रंट बनाने की योजना रुकने के आसार

उपराज्यपाल की कई योजनाओं पर लग सकता है ब्रेक

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। यमुना नदी में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी बाढ़ आने के कारण उपराज्यपाल की कई योजनाओं पर ब्रेक लगने के आसार हो गए हैं। खास तौर पर उनकी यमुना के किनारे गुजरात की साबरमती नदी जैसा रिवरफ्रंट बनाने की योजना जमीन पर आने से रह सकती है।

उपराज्यपाल ने यमुना नदी का रिवरफ्रंट बनाने के लिए इस साल की शुरुआत में डीडीए को जिम्मेदारी सौंपी थी। डीडीए के अनुसार, उपराज्यपाल के निर्देश के बाद यमुना पर रिवरफ्रंट बनाने के लिए पूर्वी दिल्ली में रिंग रोड और एनएच-24 की क्रॉसिंग के पास एक स्थान को चुना गया है और उसकी योजना बनानी शुरू कर रखी है। योजना को पूरा करने के लिए चार साल का लक्ष्य रखा गया है, मगर हाल ही में बाढ़ आने के बाद उपराज्यपाल की इस योजना पर ब्रेक लग सकता है, क्योंकि इस योजना के बारे में सोचने के दौरान किसी को यमुना में इस तरह की बाढ़ आने के कयास नहीं थे।

राजधानी में वर्ष 1978 के बाद दिल्ली में बाढ़ नहीं आई थी। डीडीए के अनुसार, यह रिवरफ्रंट बनाने के पीछे यमुना नदी को आकर्षक बनाने की मंशा है। इसके अलावा यमुना नदी के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने, लोगों को यमुना और प्रकृति से जोड़ने, यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने और वन्यजीवों को सहारा देने वाले पौधों की विविध प्रजातियां लगाने की भी योजना है।

इससे पहले शीला सरकार के समय भी यमुना नदी के किनारे को विश्वस्तरीय रूप से विकसित करने का निर्णय हुआ था और यमुना रिवरफ्रंट को विकसित करने की योजना बनाई गई थी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। यमुना नदी पर बनाया गया सिग्नेचर ब्रिज भी उसी योजना का हिस्सा था, लेकिन रिवरफ्रंट बनाने की योजना खटाई में पड़ गई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। उसने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में इस योजना को शामिल किया था। इसके बाद आप ने सरकार बनाने के बाद इस योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, मगर इस योजना पर कार्य शुरू नहीं हो पाया। दरअसल इस योजना के संबंध में कई संबंधित विभागों से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) नहीं मिल सकी थी।

डीडीए की कई योजनाओं पर संकट

डीडीए कई वर्षों से यमुना नदी को आकर्षक बनाने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रहा है, वहीं वीके सक्सेना के उपराज्यपाल बनने के बाद उसने कई नई योजनाओं पर कार्य शुरू किया, मगर हाल ही में यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण उसकी ये भी योजना पानी में डूब गई।

खासकर विभिन्न प्रजातियों के पौधों के नष्ट होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न पार्कों के भी बर्बाद होने का अनुमान है। इस संबंध में यमुना नदी का पानी उतरने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। वर्तमान में डीडीए यमुना वाटिका, यमुना वनस्थली, घाट एरिया, मयूर नेचर पार्क, ईको टूरिज्म एरिया, हिंडन सरोवर, असिता ईस्ट, कालिंदी अविरल, कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क, अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क आदि योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा उपराज्यपाल ने इस साल यमुना नदी से जुड़ी योजनाओं के लिए डीडीए के बजट में करीब चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
WEDNESDAY, 19 JULY, 2023 | NEW DELHI
----------DATED----------

Yamuna water level in Delhi drops below danger mark

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The water level of the Yamuna in Delhi on Tuesday followed a downward trend and dropped below the danger mark of 205.33 metres by 8 pm, the Central Water Commission's data showed.

On the other hand, rains lashed several parts of Delhi on Tuesday even as parts of the city continued to grapple with a flood-like situation due to a swollen Yamuna. Continued on P4

Yamuna

Lajpat Nagar, East of Kailash area in south Delhi, parts of central Delhi including the Delhi Secretariat area, among other areas, received rainfall.

The weather department had forecast moderate rain in the national Capital on Tuesday. The minimum temperature in the city settled at 27.4 degrees Celsius. The humidity level in the morning stood at 89 per cent. The maximum temperature is expected to hover around 33 degrees Celsius.

The river water level showed a slight increase on Monday due to rains in catchment areas upstream of the national Capital.

According to the CWC's flood-monitoring portal, the water level is expected to drop to 205.15 metres by 7 am on Wednesday.

The Wazirabad water treatment plant, where operations were hit due to inundation of a pump house, has also started working at full capacity, Chief Minister Arvind Kejriwal said.

A Delhi Jal Board (DJB) official said the water supply in the city is near normal.

"There is a shortage of only 10-12 million gallons of water per day (MGD) due to inundation of some tube wells in the river floodplains at Palla," he said.

The DJB extracts around 30 MGD from tube-wells installed in the Palla floodplains.

The river has been receding gradually after peaking at 208.66 metres on Thursday. However, a minor fluctuation in the water level cannot be ruled out due to rain in the upper reaches.

The inundation of a pump house at Wazirabad due to the swollen Yamuna had impeded operations at Wazirabad, Chandrawal and Okhla water treatment plants, leading to a 25 per cent drop in the water supply.

The Okhla WTP began operating on Friday, and Chandrawal on Sunday.

Kejriwal said in a tweet on Tuesday: "Wazirabad Water treatment plant has also started working at full capacity. Now all WTPs are working at full capacity. DJB worked very hard. Thank you DJB!"

Parts of the city have been grappling with waterlogging and flooding issues for a week now.

Initially, a downpour caused intense waterlogging on July 8 and 9, with the city receiving 125 per cent of its monthly rainfall quota in just two days.

Subsequently, heavy rains in the upper catchment areas, including Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Haryana, led to the Yamuna swelling to record levels.

The river reached 208.66 metres on Thursday, surpassing the previous all-time record of 207.49 metres set in September 1978 by a significant margin.

The river breached embankments and penetrated deeper into the city than it has in over four decades.

Friday marked a turning point as the raging Yamuna and the resulting backflow of foul-smelling water from drains spilt into prominent locations such as the Supreme Court, Raj Ghat, and the bustling intersection at ITO.

Prior to the misery on Friday, the river water had already reached the rear ramparts of the Red Fort and inundated one of the city's major bus terminals at Kashmere Gate.

The Ring Road, constructed partially over floodplains, remained closed for three consecutive days near Kashmere Gate last week.

With the situation deteriorating every passing hour last week, Kejriwal had urged the Centre to intervene and the Delhi Police imposed Section 144 of the CrPC in flood-prone areas to prevent public movement there.

The Army was called in for the first time since the 2010 floods to repair a broken flow regulator at drain no. 12, the reason behind the flooding in central parts of the capital on Friday.

The consequences of the floods have been devastating with over 26,000 people evacuated from their homes. The losses incurred in terms of property, businesses, and earnings have amounted to crores.

Experts attribute the unprecedented flooding in Delhi to encroachment on floodplains, extreme rainfall occurring within shorter durations, and silt accumulation that raised the riverbed.

The low-lying areas near the river in the northeast, east, central, and southeast districts, inhabited by around 41,000 people, are considered prone to flooding.

A study on "Urban Flooding and its Management" by the Irrigation and Flood Control Department identifies east Delhi under the floodplain region and highly vulnerable to floods.

Despite this, encroachment and development have occurred at a rapid pace in the ecologically sensitive region over the years.

Letters exchanged between the Delhi Forest Department and the primary land-owning agency in the city, Delhi Development Authority, show that 2,480 hectares of land in the Yamuna floodplains have been encroached upon or developed since 2009.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली।
बुधवार, 19 जुलाई 2023

बाढ़ से लाखों की घास और हज़ारों पौधे भी हुए बर्बाद

दिल्ली में आई बाढ़ का असर न सिर्फ यहां के लोगों पर पड़ा है, बल्कि यमुना किनारे डिवेलप हो चुके या हो रहे प्रोजेक्ट्स पर भी हुआ है। इसका ताजा उदाहरण असिता ईस्ट और इसके जैसे कई प्रोजेक्ट हैं। महज दस महीनों में यमुना के किनारे असिता ईस्ट पार्क को डिवेलप किया गया, लेकिन अब यहां हर तरफ पानी नजर आ रहा है। यहां लगे 4 हजार से अधिक पौधे और 33.5 लाख की रिवराइन घास पानी में बर्बाद हो चुकी है।

File Photo

यहां एंटरटेनमेंट जोन के साथ पैदल चलने के रास्ते, झील और सभा आदि के लिए जन सुविधाएं व खुली जगह भी हैं, अभी हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है

■ **आईटीओ के** पास बने 197 हेक्टेयर जमीन पर बने असिता ईस्ट पार्क को मेन रोड के साथ 100 से 500 मीटर क्षेत्र को ग्रीनवे के तौर पर विकसित किया गया था। यहां एंटरटेनमेंट जोन के साथ पैदल चलने के रास्ते, झील और सभा आदि के लिए जन सुविधाएं व खुली जगह भी हैं। साथ ही सेल्फी पॉइंट, रिवराइन घास, पौधे भी लगाए गए थे। बाढ़ आने पर इकोलॉजिकल जोन में अब सिर्फ पानी ही पानी है। वहीं इन प्रोजेक्ट में से बांसेरा को ही थोड़ा कम नुकसान हुआ है क्योंकि वह कुछ उंचाई पर है लेकिन वहां भी नुकसान हुआ है।

करोड़ों के नुकसान की है आशंका

डीडीए अधिकारी के अनुसार यमुना में आई बाढ़ से कई प्रोजेक्ट में करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। सही आकलन होने के बाद ही नुकसान का पता चल सकेगा। अब यहां काम शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी ताकि दोबारा इस तरह के हालात न बनें। पुरानी गलतियों से बचा जा सके।

प्रोजेक्ट्स का एक्सपर्ट कर रहे थे विरोध

इन प्रोजेक्ट का शुरू से ही एक्सपर्ट विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार इनके नाम पर यमुना की जैव विविधता को बदलने की कोशिश हो रही है। SANDRP (साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर्स एंड पिपल्स) के भीम सिंह रावत के अनुसार उन्होंने डीडीए के चेयरमैन व एलजी वीके सक्सेना को अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थीं। दूसरे एक्टिविस्ट भी इस तरह के विकास के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना है कि अब डीडीए को दो सालों की रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए कि यहां कितना पैसा लगा और बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है।

दिल्ली में यमुना के किनारे डिवेलप हो रहे प्रोजेक्ट्स पर हुआ असर

4 हजार से अधिक पौधे असिता ईस्ट में बाढ़ से खराब हो गए हैं

197 हेक्टेयर में बने इस पार्क को 10 महीने में डिवेलप किया था

इन प्रोजेक्ट्स पर पड़ा है असर

प्रोजेक्ट	कुल बजट (करोड़)
असिता ईस्ट	13.29
कालिंदी अविरल	13.00
कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क	7.58
असिता वेस्ट	15.25
अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क	31.03
घाट एरिया	13.73
(कुदेशिया घाट, सूर घाट, इको ट्रेल और यमुना बाजार)	
यमुना वनस्थली	11.12
मयूर नेचर पार्क	82.20
इको टूरिज़म एरिया	86.73
(गीता कॉलोनी से आईटीओ बैराज)	
हिडन सरोवर	1.48

नोट : इनमें से सबसे अधिक नुकसान असिता ईस्ट और घाट एरिया में हुआ है।

बजट में 405 करोड़ रुपये मंज़ूर किए थे

हाल में असिता ईस्ट में जी-20 का डेलिगेशन पहुंचा था

डीडीए इन प्रोजेक्ट्स पर किस तेजी से काम कर रहा था उसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि 29 मार्च को इस साल पेश हुए डीडीए के बजट में यमुना बाढ़ क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स के लिए भी 405 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। असिता ईस्ट प्रोजेक्ट में जी-20 के डेलिगेशन के साथ मीटिंग का आयोजन भी हुआ था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2023 दैनिक जागरण DATED----------

बाढ़ से सबक लेंगे?

यमुना खादर हो या हरनंदी का डूब क्षेत्र यहां की बसावट कभी बड़ा खतरा बन सकती है। अभी बाढ़ जैसे हालात बने तो हाहाकार मचने लगा, लेकिन सवाल यही है क्या हम अब इस घटना से सबक लेंगे? आगे से कभी डूब क्षेत्र में बसावट नहीं करेंगे? क्या सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन इस क्षेत्र में लोगों को वापस नहीं बसने देगा? क्योंकि वर्तमान में डूब क्षेत्र में जितना बड़ा आबादी का हिस्सा बस गया है यदि वैसा ही रहा तो भविष्य में खतरा और प्रलयकारी होगा। अभी तक राजनीतिक प्रशासनिक कोई हस्तक्षेप नहीं दिखता, यही कारण है कभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और अदालत के आदेश भी यहां बौने ही साबित हुए हैं।

- दिल्ली में यमुना किनारे कोई फार्म हाउस नहीं है। पक्के मकान और झुग्गियों की संख्या और इनमें रहने वालों का कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है। अलबत्ता, डीडीए यहां से हजारों झुग्गियां हटा चुका है।
- दो वर्षों के दौरान यमुना खादर से अतिक्रमण हटाने के लिए हाई कोर्ट और एनजीटी के निर्देश पर कई बार की गई कार्रवाई, फरवरी से अब भी जारी है। सिग्नेचर ब्रिज से आइटीओ बैराज तक ज्यादातर अतिक्रमण हटाया जा चुका।

9,000 हेक्टेयर यमुना खादर क्षेत्र वर्ष 2009 में।

2,500 हेक्टेयर में है अतिक्रमण

1,300 हेक्टेयर ही बची डीडीए के अनुसार।

विकल्प : डीडीए का कहना है कि यमुना खादर में लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं तो उन्हें कहीं और बसाने की व्यवस्था या विकल्प वह क्यों करेंगे?

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा किए गए चालान

साल	चालान	कितने के	रिकवरी अमाउंट
2018	1	50,000	शून्य
2019	186	90,40,000	22,92,500
2020	54	21,30,000	5,95,000
2021	776	1,22,95,000	21,10,000
2022	1,167	2,75,25,000	15,25,000
2023 (अप्रैल तक)	616	68,20,000	शून्य
कुल	2,801	5,78,60,000	65,22,500

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने चालान करके जुर्माना तो बहुत लगाया, लेकिन रिकवरी की रफ्तार धीमी रही

11.2% रिकवरी हुई

89.8% रिकवरी ही नहीं हुई

फरीदाबाद : यमुना व हरनंदी के किनारे अतिक्रमण

- बसंतपुर, इस्माइलपुर, भूपानी, ददसिया, लालपुर सहित अन्य गांव में पक्के निर्माण हो गए।
- 5000 अवैध निर्माण
- 200 से अधिक फार्म हाऊस और पक्के निर्माण
- 20 हजार आबादी बसी है।
- 20 बार कार्रवाई हुई पांच साल में जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट व नगर निगम की टीम द्वारा।

गाजियाबाद

3 हजार मकान बने हुए हैं हरनंदी के किनारे।

15 हजार की आबादी रहती है झुग्गियों, मकानों व फार्महाउसों में।

200 से अधिक नोटिस जारी।

विकल्प : आसरा योजना व पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों में शिफ्ट करने का कार्य हो सकता है।

गौतमबुद्ध नगर

यमुना किनारे अवैध फार्म हाउस, हरनंदी किनारे पक्के मकान बनाये गए हैं। क्रिकेट स्टेडियम, गोशाला, पशु पक्षियों डाक्टरों की क्लीनिक संचालित हो रहे हैं।

- 10 हजार झुग्गी
- 500 गोशाला
- 5,000 अवैध फार्म हाउस
- दो से अधिक क्रिकेट स्टेडियम
- 11 हजार से अधिक पक्के मकान हरनंदी क्षेत्र में
- 2 लाख से अधिक लोग रह रहे हैं
- 250 फार्म हाउस नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त किए, पांच लाख वर्ग मी. जमीन हरनंदी की कब्जा मुक्त कराई।
- एफआइआर नहीं हुई न किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई।

विकल्प : कहीं और बसाने का नहीं कोई विकल्प।

इनपुट : दिल्ली-एनसीआर जागरण इन्को

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2023

बैराज के सामने बनी नर्सरी से यमुना का बहाव प्रभावित

बैराज के बंद गेटों के एक ओर नर्सरी और दूसरी ओर गाद जमा होने से बने टीले के कारण भी यमुना का बहाव प्रभावित हो रहा है। हरियाणा के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ने मई 2014 में ही डीडीए को पत्र लिखकर इसे यमुना के हिस्से का अतिक्रमण बताया था और कहा था कि इस नर्सरी के करण यमुना का बहार प्रभावित होता है। बाकायदा मौके की फोटो भेजकर डीडीए से नर्सरी हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इस पर डीडीए ने कार्रवाई नहीं की। इस मामले पर डीडीए से जवाब मांगा गया है, जो नहीं मिल सका।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2023 EWSPAPERS

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 19 जुलाई 2023

राजनीति बंद हो, खादर क्षेत्र में अब नहीं होने दें बसावट

दिपिन्दर कपूर
कार्यक्रम निदेशक (जल), सेंटर फार साइंस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई)

आज यमुना में उफान और बाढ़ के जो हालात दिख रहे हैं उसके गुनहगार हम ही हैं। किनारे नोंचते-नोंचते रेतीली जमीन पथरीली होती चली गई और सबने आंखें मूंद लीं। राजनीति का जितना मुनाफा दिखा उतनी बसावट यमुना की तलहटी तक बढ़ती गई। यहां अब एक बार फिर अतिक्रमण नहीं हो इसके लिए सबसे जरूरी है राजनीति पर लगाम लगाना। यमुना का बाढ़ क्षेत्र ही नहीं, तमाम अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण नेताओं की शह पर ही होता रहा है। बैराज के रखरखाव में नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। यमुना में गाद की स्थिति को लेकर अध्ययन करना चाहिए, बाढ़ क्षेत्र में भू जल रिचार्ज को लेकर आकलन करना चाहिए एवं यमुना में और गंदगी या सीवरेज न जाए, इसके लिए भी कारगर व्यवस्था बनानी चाहिए। राजधानी में यमुना के किनारों से काफी छेड़छाड़ की गई है। समय के साथ वहां अतिक्रमण हुआ, निर्माण हुआ। यमुना में हर 50 साल में बाढ़ आने का इतिहास है। इसलिए वह बाढ़ अभी बाकी है। बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए यमुना किनारे बने सरकारी निर्माण को हटाना होगा।

एक बड़ी समस्या यह भी है कि 22 किलोमीटर की यमुना में 29 पुल बन गए हैं। यह पुल भी नदी को बांधने का काम कर रहे हैं। यह पुल नदी के लिए अस्थाई बांध का काम करते हैं और नदी में पीछे की तरफ पानी के स्तर को बढ़ाते हैं। जो पुल बन चुके हैं उन पर शोध करने की जरूरत है और उनकी क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। नए पुलों की जरूरत यमुना में नहीं है। जिन्हें रोक सकते हैं उन्हें रोक देना चाहिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम और वर्षा जल संचयन प्रणाली दोनों ही बेहद खराब हैं। वर्षा का पानी अधिक मात्रा में बहते हुए जमीन के अंदर न जाकर नदी में आ रहा है। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, झीलों को रिवाइव करना, ग्रीन स्पेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है।

पिछले कुछ सालों से डीडीए यमुना के इकोसिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है। सुंदरीकरण के नाम पर यमुना के किनारे चिनार, बांस, घास आदि लगाने का काम कर रहे हैं। खादर इसके लिए बना ही नहीं है। खादर में पेड़ नहीं लगाने चाहिए। न ही वहां किसी भी तरह के अस्थाई या स्थाई निर्माण की जरूरत है। इस तरह के काम तुरंत बंद कर देने चाहिए। डीडीए को अब श्वेतपत्र लाना चाहिए कि दो साल में कितना पैसा इसमें खर्च किया गया, बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हुआ।

हरियाणा और उत्तराखंड में अपस्ट्रीम यमुना में डैम और बैराज काफी अधिक हैं। इनसे कैचमेंट एरिया में काफी अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी का बाढ़ क्षेत्र करीब पांच से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है और यह इस अतिरिक्त पानी को आसानी से बहते हुए आने की जगह देता है। इसलिए पहले किनारों पर बाढ़ की स्थिति नहीं आती थी। अब आइटीओ के पश्चिमी किनारे पर तो बाढ़ क्षेत्र है ही नहीं। इस पर अतिक्रमण हो गया या यह विकसित हो गया। विचारणीय पहलू यह भी है कि बाढ़ क्षेत्र में बहुत अधिक अतिक्रमण हो गया है। पानी जो पहले फैलता था, जिससे बाढ़ रुकती थी वो अब खत्म हो रहा है। दूसरा, यमुना में गाद काफी अधिक है। इसकी वजह से रिवर बेड ऊपर आ गया है और कम पानी से ही बाढ़ आ रही है। तीन से चार राज्यों से गुजरने वाली यमुना को लेकर राज्यों के बीच में भी तालमेल नहीं है। हथनीकुंड बैराज के पानी को लेकर राज्यों में समन्वय होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को बीते कई सालों से अपग्रेड नहीं किया गया है। बरसात तो अब तेज होने लगी है। वर्षा को तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करना, बाढ़ क्षेत्र को बेहतर ढंग से रखरखाव करना और राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर बाढ़ से राहत मिलेगी।

-संजीव गुप्ता
से बातचीत पर आधारित

दिल से दिल्ली

जब बहादुरशाह जफर को बचाया था यमुना ने

1857 के गदर में, मेरठ के विद्रोहियों ने कश्मीरी गेट से दाखिल न होकर दिल्ली दरवाजे से इसलिए दाखिल हुए,क्योंकि बचाव के लिए सामने यमुना नदी थी। बहादुरशाह जफर को भी यमुना नदी ने ही बचाया, गोरी हुकूमत की फौज ने दिल्ली की घेराबंदी कर ली। तो बादशाह जफर नदी के रास्ते एक नाव पर सफर करके सुरक्षित हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। यमुना जी बादशाहों से लेकर गुरबत में रहने वाले सबके लिए एक वक्त मनोरंजन का साधन थीं। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि शाहजहां जमुना में नाव चलाकर लुत्फ उठाता था। वही दिल्ली का गरीब अवाम जमुना जी के घाटों की बुलंदियों से छलांग लगाकर छपाक से पानी में कूदकर तैर कर आगे निकलने की ताकत का इजहार करते थे। नावों में बैठकर नौजवानों की टोली दूसरी नाव में सवार टोली से टक्कर लेने के लिए जोर-जोर से चप्पू तथा लंबे बांस के सहारे आगे निकालने का जी तोड़ प्रयास करती थी। *क्या नहीं बना यमुना किनारे खादर पर* ▸▸ पेज 7

देखें हमारी वेबसाइट
nbtdilsedilli.com

दिल से दिल्ली

क्या-क्या नहीं बना यमुना किनारे खादर पर

राजधानी होने के कारण बढ़ती हुई आबादी तो इसकी जिम्मेदार है ही। दिल्ली के यमुना किनारे खादर में लगभग 36 सौ कॉलोनिया बसा दी गईं। यमुना के अधिकार क्षेत्र वाली जमीन पर स्वामीनारायण मंदिर, कॉमनवेल्थ अपार्टमेंट, दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम इंटरस्टेट बस अड्डा का डिपो बिजली घर जैसी इमारतें बना दी गई। अनुमान है कि यमुना तकरीबन डेढ़ मील पूरब की तरफ सरक गई। यमुना की बदहाली को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण, बाढ़ सिंचाई विभाग, दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना से प्रदूषण खत्म करने के लिए बड़ी स्कीमें बनाई, सर्वे किए, रिपोर्ट बनाई परंतु वह कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रही। वॉटर टैक्सी चलाने का प्लान भी तैयार हुआ। डीडीए भी अब तक करीब दो दर्जन मास्टर प्लान बना चुका है। हर प्लान में यमुना को लेकर कई प्रावधान किए गए, परंतु वही ढाक के तीन पात।